© UNIVERSAL RESEARCH REPORTS | REFEREED | PEER REVIEWED
ISSN : 2348 - 5612 | Volume : 05 , Issue : 03 | January – March 2018

भारतीय सर्विधान में छात्रों के संवैधानिक अधिकार : एक विवेचना

[1]Kalpana Dalela, [2]Dr Beena Singh

[1]Research Scholar, Department of education, Mahatma Jyoti Rao Phoole University, Jaipur (Rajasthan)

[2]Assistant Professor, Hari Bhau Upadhyay mahila Shikshak Mahavidhyalaya, MDS University, Ajmer

ISSN : 2348-5612 © URR

सार : भारतीय कानून ने 'छात्र' शब्द का कोई सांविधिक अर्थ परिभाषित नहीं किया है। भारत के नागरिक के लिए उपलब्ध कानूनी अधिकार सामान्य तौर पर छात्रों के लिए उपलब्ध हैं जो भारत में एक छात्र के लिए उचित तरीके से अपने अधिकारों का उपयोग करने के लिए चुनौतीपूर्ण बनाता है।

एलपीजे एंड पार्टनर्स से प्रसाद जैन और अपूर्व चंदोला के अनुसार, शब्द छात्र अभी तक वैधानिक रूप से परिभाषित नहीं हुआ है और भारत में छात्र अधिकारों के लिए किसी भी संहिताकृत कानून की कमी भी है, जिससे आज विद्यार्थियों के लिए एक व्यवस्थित तरीके से अपने अधिकारों को लागू करना मुश्किल हो जाता है। तौर तरीका। वे कहते हैं, "छात्रों की जरूरतों पर ध्यान देने वाले कानून सरकार द्वारा शिक्षा, खेल और अन्य क्षेत्रों में पूर्वाग्रहों से बचने के लिए बहुत आवश्यक अभ्यास है। संहिताबद्ध कानून उन्हें संस्थानों, व्यक्तियों या व्यक्तियों की मनमानी क्रिया से बचाने में मदद कर सकते हैं। जबकि एक ही प्रक्रिया के अधीन है, जागरूकता एक छात्र के लिए अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है

इस लेख में भारत के हर छात्र के कानूनी एवं संवैधानिक अधिकारों के बारे में कुछ जानकारी प्रस्तुत की गयी है |

अनुमान है कि भारत की कुल आबादी का लगभग 15% छात्रों में शामिल है इसलिए, छात्रों को प्रगति या पतन की चरम सीमाओं के लिए एक राष्ट्र को अग्रणी बनाने में सक्षम एक महान क्षमता बल का गठन होता है। कोई आश्चर्य नहीं कि हर देश अपनी शिक्षा और उचित विकास के लिए करोड़ों रुपए खर्च करता है। हर राष्ट्र का भविष्य उनके छात्रों पर निर्भर करता है।

एक छात्र का प्राथमिक कर्तव्य सीखना और ज्ञान प्राप्त करना है। उनका मुख्य कर्तव्य उनकी बुद्धि को सुधारने और उनकी मानसिक क्षमताओं को चौड़ा करने के होते हैं। दुर्भाग्य से, कई छात्र इस लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपने विद्यालय के दिनों का खर्च बेकार तरीके से अपना समय व्यतीत कर रहे हैं और अपना समय बिताते हैं। केवल बाद में वे अपनी मूर्खता का नतीजा जानते हैं।

लेकिन तब बहुत देर हो चुकी है स्कूल एक मंच है जिसमें छात्रों को जीवन के अच्छे लक्षण जैसे अनुशासन, आज्ञाकारिता, कर्तव्य, परिश्रम, बड़ों के प्रति सम्मान, ईमानदारी, देशभक्ति आदि सीखना है। स्कूल इन गुणों के विकास के लिए कई अवसर प्रदान करता है। यह प्रत्येक छात्र का कर्तव्य है कि वह जीवन के इन गुणों को प्राप्त कर सकें जिससे भविष्य में उसे अच्छी स्थिति में खड़ा किया जा सके।

छात्रों का एक और महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि उन्हें कैरियर के लिए तैयार करना चाहिए जो वे आगे बढ़ना चाहते हैं। यह स्कूल के जीवन में है कि भविष्य के कैरियर में जड़ें लगती हैं स्कूल की जिंदगी के दौरान, एक व्यक्ति की क्षमताओं, सीमाएं और उपलब्ध विभिन्न व्यवसायों के बारे में पता हो जाता है इसलिए, इस चरण के दौरान उन्हें अपने दिमाग को बनाते रहना चाहिए कि उन्हें जीवन में क्या होना चाहिए। किसी के करियर का उचित विकल्प बनाने के लिए स्कूल जीवन सही समय है

छात्र समाज के संरक्षक हैं। समाज में मौजूद सभी बुराइयों से लड़ने का उनका कर्तव्य है वे देखते हैं कि अन्याय, असमानता, उत्पीड़न, शोषण, भ्रष्टाचार, राजनीति का अपराधीकरण, सांप्रदायिकता, जातिवाद, जनता के पैसे का दुरुपयोग आदि जैसी बहुत ज़िम्मेदारी है। छात्रों के समाज के इन बुराइयों का विरोध करने के लिए बहुत ताकत है।

सामाजिक कार्य के जरिए समाज के कम भाग्यशाली सदस्यों को मदद करने के लिए विद्यार्थियों की भी बड़ी जिम्मेदारी है। वे पास के गांवों के अशिक्षित बच्चों को पढ़ाने, इलाके के गरीब लोगों के लिए मकान बनाने, ड्राइविंग करने, विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर जन जागरूकता पैदा करने, आदि द्वारा महान सेवाएं प्रदान कर सकते हैं।

भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार

कानून के एक छात्र द्वारा दायर की गई याचिका में, सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्ति की स्वतंत्रता और हमारी सरकार के लोकतांत्रिक स्वरूप के दृष्टिकोण से दोनों ओर से भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व को निर्धारित किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतांत्रिक संविधान के तहत भाषण और राय की अभिव्यक्ति की सर्वोच्च महत्व है जिसमें विधायिकाओं और सरकारों की रचना में बदलाव की परिकल्पना की गई है और उन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए।

सुचना का अधिकार :

सूचना भागीदारी की शुरुआत है यदि बच्चे में पर्याप्त जानकारी नहीं है तो वह प्रभावी ढंग से भाग नहीं ले सकते। ऐसी भागीदारी सार्थक होनी चाहिए किसी को अधिकार के बजाय मौके के संदर्भ में बात करनी है क्योंकि बच्चा नहीं जानता है और भाग लेने के बारे में नहीं पता है। बिना सहभागिता उसके भीतर का अनुशासन विकसित नहीं होगा। ड्राइव करने का अधिकार, वह हो सकता है लेकिन ड्राइव करने का मौका, वह नहीं मिल सकता है जांचकर्ताओं को अपने उत्तर पुस्तिकाओं का निरीक्षण करने की अनुमति देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सूचना का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 9 (1) (ए) और इस तरह के अधिकार के रूप में "भाषण और अभिव्यक्ति" की स्वतंत्रता का एक पहलू है राज्य की ब्याज और सुरक्षा में छूट और अपवादों के लिए उचित प्रतिबंध के अधीन है।

समानता का अधिकार :

दाखिले के दौरान शैक्षिक संस्थानों द्वारा पालन किए जाने वाले सिद्धांतों को बिछाने के दौरान, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया है कि यदि प्रतियोगी उम्मीदवारों को समानता और समान उपचार के अधिकार का उल्लंघन किया गया है, तो यह पूरी तरह से न्यायसंगत होगा और उचित होगा ताकि उन्हें असाधारण राहत मिल सके |

शिक्षा का अधिकार:

यह एक भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 ए के तहत यू.पी. राज्य में दोहराया गया मौलिक अधिकार है। बनाम भूपेंद्र नाथ त्रिपाठी 2010 (13) एससीसी 203 (पैरा 11)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार:

दिल्ली उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच ने दिल्ली स्कूल शिक्षा नियम 1 9 73 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए एक नियम का उल्लंघन करते हुए कहा कि बच्चों को स्कूलों में शारीरिक सजा नहीं दी जानी चाहिए और उन्हें स्वतंत्रता और गरिमा के वातावरण में शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। भारतीय संविदा अधिनियम: एक छात्र जिसने बहुमत से प्रवेश किया है, अर्थात 18 वर्ष भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के तहत एक अनुबंध में प्रवेश कर सकते हैं। एक शैक्षिक ऋण लेने के दौरान, किसी छात्र को स्वीकृति देने वाले बैंक के साथ अनुबंध संबंधी समझौते में प्रवेश करना पड़ता है या एक आवासीय संपत्ति के मालिक के साथ पट्टा समझौते में प्रवेश करना पड़ता है।

फौजदारी कानून:

7 वर्ष से कम आयु के छात्र भारतीय दंड संहिता के तहत आपराधिक दायित्व से छूट प्राप्त करते हैं और 7 से 12 वर्ष के बीच उत्तरदायित्व छात्र की परिपक्वता पर निर्भर होगा।18 वर्ष से कम आयु के छात्र बाल न्यायालय (बच्चों के संरक्षण और देखभाल) अधिनियम, 2015 की परिभाषा के तहत आते हैं और वयस्क अपराधियों के रूप में इलाज किए जाने से संरक्षित होते हैं, जब तक कि उन्हें कानून में परिभाषित एक जघन्य अपराध नहीं मिलते। कानून के साथ संघर्ष में ऐसे छात्रों के साथ व्यवहार करते समय, कुछ सिद्धांतों को अधिनियम के धारा 3 के तहत सरकारी अधिकारियों द्वारा पालन करना पड़ता है जैसे कि मासूमियत, सिद्धांत, समानता और गैर-भेदभाव, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत आदि के सिद्धांत।

सन्दर्भ :

1. अकमार्क्स, एसएस 1998. मानव अधिकार शिक्षा - उपलब्धि और चुनौतियां, पेरिस, यूनेस्को
2. अरोड़ा, जी.एल., पांडा, प्रणति। 2000. भारत में शिक्षक शिक्षा के 50 वर्ष: स्वतंत्रता विकास, नई दिल्ली, एनसीईआरटी के बाद।
3. बउर, जे आर और बेल, डीए (एड्स।) 1 999। ईस्ट एशियाई चुनौतियां फॉर ह्यूमन राइट्स, न्यूयॉर्क, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस
4. डिन्सडेल, जे। 1 9 80. "मानव अधिकारों के सम्मान को बढ़ावा देने के लिए शिक्षण और शिक्षा: मानव अधिकारों के क्षेत्र में शिक्षण, शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए यूरोप की हालिया प्रयासों की परिषद," राजनीतिक शिक्षा के इंटरनेशनल जर्नल, 2, 163 -175।
5. 2001. मानव अधिकार शिक्षा शिक्षक शिक्षकों (मूलभूत कर्तव्यों, मानवाधिकार और शांति शिक्षा) के लिए स्व-शिक्षा सामग्री नई दिल्ली, एनसीईआरटी
6. 2004. भारतीय शिक्षा जर्नल में "मानव अधिकार शिक्षा: दृष्टिकोण और चुनौतियां" नई दिल्ली, एनसीईआरटी